(b) if so, the previous rates, factory wise; and

(c) the revised rates, factory-wise ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI BHANU PRAKSH SINGH) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

श्री राम किशन गुप्त : क्या मन्त्री महोदय एश्योरेस देंगे कि मौजूदा कंट्रोल पालीसि जारी रहेगी और सिमेंट के रेट बढ़ाये नहीं जायेंगे प्रेशर के बावजूद भी ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : यह अभी विचाराधीन है ।

श्री राम किशन गुप्त : मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है उससे यह पता नहीं चलता कि साहू जैन की तरफ से क्या सजेशन आई थी । क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने अपनी सजैशन में क्या रेट दिया था और वह क्या चाहते थे ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): जैसा कि अभी बताया गया है, कोई कीमत नहीं बढ़ाई गई हैं । इंडस्ट्री की तरफ से जो रिप्रेजेन्टेशन वगैरह हम को मिले हैं, उन सब पर गौर किया जा रहा है ।

SHRI JYOTIRMOY BASU : Last time how much did you get ? Rs. 1½ crores.

SHRI SEZHIYAN : I hope, the Government are aware that the Madras High Court last December had struck down the Cement Control Order in respect of uniform price of Rs. 100 allowed to all the factories. In view of the High Court's order striking down the uniform price given by the Government, I want to know whether Government are going to revert to the old three tier price system or whether they will go into the question of how the price will be given to the various units.

SHRI F. A. AHMED : Government is aware of the order passed by the Madras High Court and Government is proposing to file an appeal and a petition for a stay order. Action will be taken after those are disposed of.

MR. SPEAKER : Next question.

SHRI KARTIK ORAON : Question No. 35

SHRI MANUBHAI PATEL : Sir, question No. 37 may also be taken up along with this.

MR. SPEAKER : All right Let question No. 37 be replied together with question No. 35.

Convertion of Narrow Gauge Line From Ranchi to Lohardaga (South Eastern Railway)

*35. SHRI KARTIK ORAON : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to convert the narrow gauge railway line from Ranchi to Lohardaga on the South-Eastern Railway into broad gauge line;

(b) if so, the details therefor;

(c) is not, the reasons therefor; and

(d) whether Government will give due consideration to the demands of the people of Lohardaga area, a hinterland of rich bauxite deposits which can give rise to the establishment of an aluminium factory ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI R. L. CHATURVEDI) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) Conversion of the Ranchi Lohardaga Narrow Gauge Section into broad gauge is not justified at present as the capacity of this Narrow Gauge Section is adequate to meet the present traffic requirements, as well as any increases likely to materialise in the near future.

छोटी रेलवे लाइनों में सुधार

*37 **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छोटी रेलवे लाइनों में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए बनाई गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त प्रतिवेदन के आधार पर सरकार ने क्या कार्यक्रम बनाया है ?

रेलवे मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी): (क) जी, हां। एक विवरण, जिसमें मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा दिया गया है, सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रख दिया गया। देखिये संख्या LT-2563/70]

(ख) इन सिफ़ारिशों पर विचार किया जा रहा है।

SHRI KARTIK ORAON : All the railway lines, whether converging to or diverting from Ranchi, the hub of industiral complexes are broad guages except this line. I would like to know from the Government the main criteria or guidelines that have been fixed for conversion of metre gauge into broad gauge.

SHRI R. L. CHATURVEDI : This particular line from Ranchi to Lohardaga was constructed in 1913 for the main object of carrying bauxite ore. I have visited the place with the hon. Member recently and the demand is that it should be converted into broad gauge. The position at present is that we can cater to the traffic requirements with the present line capacity. If and when the demand is more and we cannot cater to it, we shall certainly consider the conversion of this into broad gauge.

SHRI KARTIK ORAON : Even though this particular line is connected to a place with very rich mineral deposits, Government is not looking after the interest of this area particularly because it is a Tribal area and they do not want any factory to come up there. That is the place where you can have aluminium factory, paper factory and all that. You are negativing that aspect. I would like to know from the Government the annual income by way of passenger fares as also feight for the carriage of bauxite from Lohardaga to Ranchi.

SHRI R. L. CHATURVEDI : As far as the first part of the question is concerned, I repudiate the allegation that since it is a Tribal area it was made an exception.

SHRI KARTIK ORAON : Otherwise why did you make an exception ?

SHRI R. L. CHATURVEDI : I can assure the hon. Member that if and when there is another aluminium factory or any other such thing which cannot be catered to by the present line capacity, we will certainly consider it. Meanwhile, I may point out that, in 1955, investigations were made and the result wasthat there was no need to convert into broad-gauge. Recently, when the Uneconmic Branch Lines Committee visited the area, they discussed with the State Government of Bihar and the State Government said that there was the potentiality of a paper mill comming up there and another aluminium factory also coming up and we assured them that, if and when, the materialised, the Railways will not lag, behind in meeting their requirements.

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जब मन्त्री महोदय और सब कमेटी के सदस्य दौरे पर ग्वालियर पधारे थे, तो ग्वालियर और अन्य कई जिलों के प्रतिनिधियों ने उन से यह प्रार्थना की थी कि ग्वालियर-भिंड नैरोगेज रेलवे लाइन को ब्राडगेज बनाया जाये और इटावा तक मिला दिया जाये, क्योंकि चम्बल नदी जल विद्युत् योजना निर्माण पर शासन ने जो करोड़ों रुपया खर्च किया है, शासन और किसानों को उस का फायदा तभी मिल सकेगा—जो कि देश की उत्पादन वृद्धि में प्रगति के लिए भी बहुत आवश्यक है जब इस लाइन को ब्राडगेज बना कर पूर्वीय और पश्चिमी भारत को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाये। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण बात को दृष्टि में रख कर इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी: जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, यह सत्य हैं कि जब मै और कमेटी के सदस्य वहां गये थे, तो वहां से इस बारे

में रिप्रेजेन्टेशन मिले थे और माननीय सदस्य से भी इस बारे में बात हुई थी। परन्तु खेद है कि आज-कल जो परिस्थिति है, उसमें हमारी कमेटी ने उस लाइन के कनवर्शन की सिफारिश नहीं की है। (व्यवधान)

श्री रवि राय : क्या परिस्थिति है ? (व्यवधान)

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी: मेरा मतलब रेलवे की आर्थिक परिस्थिति से है। इसके अलावा वहां की जो ट्रैफिक रेवन्यायरमेंट है, वह उससे मीट हो जाती है। लेकिन इस सिलसिले में मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उसकी इम्प्रूवमेंट और ट्रैक रीन्यूअल के लिए रीकमेंडेशन की गई थी, ताकि वहां के लोगों को ज्यादा सुविधा हो और इस बारे में जांच की जा रही है। वह रिपोर्ट 19 दिसम्बर को सभा पटल पर रख दी गई थी। उस की अंग्रेजी की प्रतियां छप गई है, जो कि जल्दी ही सदस्यों को दे दी जायेंगी। उस रिपोर्ट का हिन्दी में ट्रांसलेशन हो रहा है।

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : क्या यह सत्य नहीं है कि जब ग्वालियर गवर्नमेंट ने इन नैरोगेज रेलवे लाइन्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपा था, तो उस की कन्डीशन बहुत अच्छी थी और साथ ही उस की बचत के 75 लाख रुपये एक मुश्त केन्द्रीय सरकार को दिये थे ? क्या यह भी सत्य नहीं है कि इस लाइन को सेन्ट्रल गवर्नमेंट को हैंड ओवर किये जाने के बाद इन बीस सालों में इस लाइन के लिए एक भी नया इंजिन या डिब्बा नहीं दिया गया है, जब कि किराया बढ़ा दिया गया है और आने जाने में लगने वाला समय पहले से दुगना हो गया है ? इन सब बातों और चम्बल योजना के उत्पात के क्षेत्र की आतंकपूर्ण डाकू समस्या को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार इस प्रश्न पर स्पेशल तरीके से विचार करने के लिए तैयार है ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, हम इस प्रश्न पर स्पेशल तरीके से विचार करेंगे। इस विषय में हम लोगों ने अपनी खास सिफारिशें दी हैं।

SHRI R. K. AMIN : May I have an assurance from the hon. Minister of Railways that in so far as States which have not achieved the target of road construction, even accordind to the Nagpur Plan, no narrow-gauge railways will be removed and, if they are removed, they will be replaced by the meter-gauge or broad-gauge lines ?

SHRI R.L. CHATURVEDI : As I said, the report is under consideration and we have not reversed the policy-decision made by the then Railway Minister, Dr. Ram Subhag Singh. We have suggested certain improvements.

SHRI R. K. AMIN : Especially I am asking of the Gujarat State where even the Nagpur Plan targets have not been achieved.

MR. SPEAKER : You did not ask any question. Still I asked him that he may give an assurance. You are still insisting on him (*Interruptions*) No Please. Please sit down.

श्री मु० अ० खां : अभी जो कमेटी अनइकानामिक लाइन्ज को देखने के लिये गई थी और जिस के चेयरमैन हमारे मन्त्री महोदय थे, क्या यह सही है कि उन्होंने यह रिपोर्ट दी है कि एटा-कासगंज लाइन को मिला दिया जाये, तब ही वह लाइन इकानामिक कन्डीशन में चल सकती है ? यह देखते हुये कि अनइकानामिक लाइन्ज को इसी हालत में चलाने में सात करोड़ रुपये का नुकसान होता है; क्या मन्त्री महोदय यह एशोरेंस देंगे कि इसी बजट में एटा-कासगंज लाइन को मिलाने के लिये कार्यवाही की जायगी और उसके लिये प्रोवीजन रखा जायगा ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : बजट कल पेश हो गया है। माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि अनइकानामिक लाइन्ज के बारे में जो रिपोर्ट थी वह जेरेगौर है। उन्होंने इसके कनेक्शन के लिये रिकमेन्ड जरूर किया है, लेकिन जैसा मैंने

अभी कहा था कि इसकी पूरी तरह से जांच हो रही है। इस बजट में अभी इसका उल्लेख नहीं है।

श्रीमती जयबिन शाह : मीटर गेज को ब्राड गेज में कन्वर्ट करने के लिये जो कमेटी बनी थी और उसने जो रिपोर्ट दी है, वह तो ठीक है, लेकिन जिन लाइनों के बारे में इन-प्रिन्सिपल तय हो गया था, मैं उनके बारे में पूछना चाहती हूं जैसे वीरम गांव से ओखा लाइन के बारे में इन-प्रिन्सिपल तय होगया था, पिछली दफा उसके प्रिलिमिनरी सर्वे को भी बजट में शामिल किया गया था, लेकिन नये बजट में फिर प्रिलीमिनरी सर्वे के लिए रख दिया है। जब प्रिन्सिपल में एक चीज एग्री हो जाती हैं और जो कमेटी बैठी थी, उन्होंने भी सिफारिश की है तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वजह है कि उसको बजट में शामिल नहीं किया गया ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : ये दोनों प्रश्न अनइकानामिक ब्रांच लाइन्ज के सम्बन्ध में नहीं उठते हैं। माननीय सदस्यों ने जो पूछा है, उसके सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि उस कमेटी की रिपोर्ट पर अभी जांच हो रही है और जल्दी ही जो निर्णय होगा वह सभा पटल पर रख दिया जायगा। जहां तक वीरम गाँव-ओखा लाइन का सवाल है, जैसा आपको मालूम है उसके प्रिलीमिनरी सर्वे के लिये कहा गया है। इसकी डिटेल्ज मैं इस वक्त बताने की स्थिति में नहीं हूँ।

श्रीमती जयबिन शाह : प्रिलीमिनरी सर्वे की बात तो बहुत सालों से चलती है इसके लिये तो इन-प्रिन्सिपल एग्री कर लिया गया था ....

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : इस वक्त मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बता सकता....

अध्यक्ष महोदय : रेलवे बजट पर बाकायदा 17 घंटे की बहस होने वाली है। उस वक्त आप को मौका मिलेगा, इसलिये इस वक्त इस क्वेश्चन-आवर को इस तरह से क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे मेम्बरों को भी इस वक्त का लाभ क्यों नहीं उठाने देते। मैं आपको रेलवे बजट पर जरूर टाइम दूंगा।

Qn. 37 is already answered.

SHRI MANIBHAI J. PATEL : He has not replied to 37 (b).

SHRI N.K.P. SALVE : Why not delete all questions on railways because we are going to have a debate on railway budget ?

MR. SPEAKER : We had enough number of questions. Therefore, I am not going to allow any further question.

SHRI MANIBHAI PATEL : Sir, question 37 (b) has not been replied to at all.

SHRI N. K. P. SALVE : My supplementary has nexus with Question No. 37. When the Committee magnanimously visited Parasia, it was represented that for economic welfare the narrow gauge line between Parasia and Nagpur should be converted into broad gauge.

MR. SPEAKER : You are a very clever lawyer. I am sorry. Next question.

Steel Outlay for the Fourth Five Year Plan

*36. SHRI PILOO MODY :
SHRI C. C. DESAI :
SHRI R. R. SINGH DEO :
SHRI D. N. PATODIA :
SHRI N. SHIVAPPA ;

Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to state :

(a) whether Government have decided to increase the steel outlay for the Fourth Five Year Plan;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether the attention of Government has been invited to a report in the 'Economic Times' of the 7th January, 1970 ?